



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]
No. 151]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2005/ज्येष्ठ 13, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2005/JYAISTHA 13, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना (मध्यावधि समीक्षा)

नई दिल्ली, 3 जून, 2005

विषय: ई यू, (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीनी टाईपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत

सं. 15/5/2005-डीजीएडी:— यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2003 की अधिसूचना संख्या 14/39/2002-डीजीएडी के द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीनी टाईपेई (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कास्टिक सोडा (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था ।

और यतः दिनांक 14 नवम्बर, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 168/2003-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच और इस वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पादक कास्टिक सोडा है जिसे आम तौर पर ई यू (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीनी टाईपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है । कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुनी, तीव्र क्षारीय तथा गंधहीन रसायन

है। कास्टिक सोडा का उपयोग लुग्दी एवं कागज के विनिर्माण, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्यूमीनियम, कॉटन, वस्त्र, शौच एवं धुलाई का साबुन, डिटरजेंट, डाईस्टफ, औषध एवं भेषज, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कास्टिक सोडा दो आकार में उत्पादित किया जाता है अर्थात् सज्जीदार पानी (लाई) और ठोस। कास्टिक सोडे के सभी आकार मौजूदा जांच की विषय वस्तु है।

कास्टिक सोडा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसे आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अनुसार शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच शुरूआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियमों के अनुसार प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी विचार करते हैं कि सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की पाटनरोधी नियमों के नियम 23 और यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) के प्रावधान के अंतर्गत इस अवस्था में मध्यावधि समीक्षा करना उपयुक्त होगा। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार संबद्ध वस्तु के एक आयातक मै0 हिन्दुस्तान लीवर लिमि0 ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करने की जरूरत को प्रमाणित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश ई यू (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीनी ताईपेई है।

5. समीक्षा के लिए आधार

आवेदक ने दावा किया है कि पाटन और क्षति दोनों की परिस्थितियां काफी परिवर्तित हो गयी हैं जिनके कारण लागू पाटनरोधी उपायों की समीक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने उल्लेख किया कि कास्टिक सोडा की कीमतें वर्ष 2004 और 2005 के बीच मोटे तौर पर 56 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं और क्लोरीन की कीमतें भी इसी अवधि के दौरान 62 प्रतिशत तक बढ़ गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप क्लोर एल्कली उद्योग को भारी लाभ हुए हैं चूंकि लागत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इस मूल जांच में प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के पैरा 106 में यह नोट किया है कि बिक्री की लागत में वृद्धि बिक्री की कीमत से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट आई। यह स्थिति अब विद्यमान नहीं है, जो कि प्रदर्शित की गई है कि क्लोर एल्कली उद्योग की लाभप्रदता में समग्र रूप में वृद्धि हुई है।

संबद्ध वस्तु के लिए सीमाशुल्क वर्ष 2000-2001 के 35 प्रतिशत से कम करके 2005-2006 के दौरान 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है जो अपने आप में समीक्षा की मांग करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन का एक कारण है। तथापि सीमाशुल्क में कटौती के बावजूद लाभप्रदता में वृद्धि होना जारी रहा जो यह प्रदर्शित करता है कि घरेलू उद्योग को कथित पाटन के कारण क्षति नहीं हो रही है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की गई संदर्भ कीमतें 271.46 अमरीकी डॉलर/मी.टन से 258.48 अमरीकी डॉलर/मी.टन के बीच है। याचिकाकर्ता आगे दावा करता है कि चूंकि जांच अवधि के दौरान आयात कीमत, इस जांच में लगाई गई संदर्भ कीमत से अधिक है इसलिए संदर्भ कीमतें निरर्थक हैं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारत में संबद्ध देशों से आयातों का पाटन नहीं किया जा रहा है। चूंकि घरेलू उद्योग को प्रकार की क्षति नहीं हो रही है इसलिए याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

6. प्रक्रिया

लागू उपाय की समीक्षा के लिए जरूरी परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि उपर्युक्त नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम की धारा 9क (5) के प्रावधान के अनुसार, परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर दिनांक 1/10/2003 की सं.14/39/2002-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों तथा दिनांक 14/11/2003 की अधिसूचना द्वारा लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित है। समीक्षा में दिनांक 1/10/2003 की अधिसूचना सं. 14/39/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

7. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 (12 महीने) तक है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और जनवरी, 2004- दिसम्बर, 2004 तक की अवधि शामिल होगी।

8. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित समझे गए आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने हेतु पृथक रूप से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)
कमरा संख्या 240
उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

9. समय-सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच सके । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा कोई प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

10. सरकारी फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार, कोई हितबद्ध पक्ष अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

क्रिस्टी फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION (Mid-term Review)

New Delhi, the 3rd June, 2005

Subject: Initiation of Mid-term Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Caustic Soda originating in or exported from EU (excluding France), Indonesia and Chinese Taipei.

No. 15/5/2005-DGAD - Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), vide Notification Number 14/39/2002-DGAD dated 1st October, 2003, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Caustic Soda (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from EU (excluding France), Indonesia and Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject countries).

And Whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 168/2003-Customs, dated 14th November, 2003.

2. Product Under Consideration

The product involved in the original investigation and this current review is Caustic Soda originating in or exported from EU (excluding France), Indonesia and Chinese Taipei. Caustic Soda is an inorganic, soapy and strongly alkaline odourless chemical. Caustic Soda finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining, etc.. Caustic soda is produced in two forms, i.e. Lye and solids. Present investigation covers all forms of caustic soda.

Caustic Soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified as per International Trade Classification [based on Harmonized Commodity Description and Coding System] under the heading 2815.11 and 2815.12. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. The Designated Authority considers that the mid term review of the anti dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of rule 23 of AD Rules and section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended. In terms of the above provision one of the importers, M/s Hindustan Lever Limited of the subject goods, have filed an application substantiating the need for mid term review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from subject countries.

4. Countries Involved:

The countries involved in the present investigations are EU (excluding France), Indonesia and Chinese Taipei.

5. Grounds for Review

The applicant claims that the conditions of both dumping and injury have changed substantially requiring a review of the anti-dumping measure in force. They have stated that the prices of Caustic Soda has increased by about 56% during 2005 from 2004 and the prices of Chlorine has also increased by 62% during the same period. It resulted into huge profits for Chlor alkali industry as the cost has gone up marginally. In this original investigation the Authority has noted at para 106 of the final findings that increase in cost of sales was more than the selling price is directly resulted in decline of profits of the domestic industry. This situation no longer exist which has been demonstrated that the profitability of the Chlor Alkali industry as a whole has increased.

1696 E.1105-2

The custom duty for the subject goods has reduced from 35% during 2000-2001 to 15% during 2005-2006 which itself is a cause for change in circumstances warranting a review. However inspite of reduction in custom duties, the profitability

has continued to increase which demonstrates that the domestic industry is not suffering injury on account of any alleged dumping.

The references prices recommended by the Designated Authority and imposed by the Ministry of Finance are in the range of US\$ 271.46/MT to US\$ 258.46/MT. The applicant further claims that this reference prices itself is redundant since the import price during the period of investigation is more than the reference price imposed in this investigation.

The applicant claims that the imports from subject countries are not being dumped in India. Therefore the applicant has requested for the need for mid term review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from subject countries as the domestic industry is not suffering any injury.

6. **Procedure:**

Having regard to the information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the final findings notified vide No.14/39/2002-DGAD dated 1/10/2003 and the Definitive anti dumping duty imposed by Notification dated 14/11/2003 is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 supra. The review covers all aspects of Notification No.14/39/2002-DGAD dated 1/10/2003 .

7. **Period of Investigation:**

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st January 2004 to 31st December 2004 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 and January 2004-December 2004.

8. **Submission of Information:**

The exporters in subject countries, their government through their Embassies/High Commissions in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

9. **Time Limit:**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of letter of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

10. **Inspection of Public File:**

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority